कांग्रेस की यह कैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनाव कार्यक्रम जारी, मतदाता सूची का अता- पता नहीं

पार्टी संविधान के मुताबिक चुनाव कार्यक्रम ब्लॉक अध्यक्ष से शुरू होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाता है, लेकिन अभी तक देश में किसी भी ब्लॉक में चुनाव नहीं हुए, हो जाते तो सूचियां जारी करनी पड़तीं

- **ब्लॉक की चुनाव प्रक्रिया के जरिए जिला प्रतिनिधि चुने जाते हैं और ब्लॉक तथा जिला प्रतिनिधि ही प्रदेश प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, इसके बाद प्रदेश प्रतिनिधि ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वैध मतदाता होता है।**

जयपुर, 9 सितम्बर (का.प्र.)। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नज़दीक आ रहा है, लेकिन यह भी तय है कि चुनाव से पहले बड़े विवाद हो सकते हैं। आशंका है कि मामला कहीं न्यायालयों में नहीं चला जाए। इसका बड़ा कारण यह है कि एक ओर तो 24 सितंबर से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, दूसरी ओर अभी तक पूरे देश में किसी भी प्रदेश के 4 प्रदेश प्रतिनिधियों की सूची जारी नहीं की गई है। जबकि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में 10 प्रस्तावक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। ऐसे में तय है कि जब सूची जारी नहीं हो रही है तो कोई भी अध्यक्ष पद का चुनाव कैसे लड़ सकता है?

कांग्रेस का चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ था उस समय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री और जयराम रमेश ने मीडिया के सामने कहा था कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव कराए जाते हैं और कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बावजूद अभी तक प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधियों की सूची जारी नहीं करना बता रहा है कि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, बल्कि गुप्त तरीके से होंगे। अब या तो सूची नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक जारी होगी या फिर जिसे भी अध्यक्ष बनाया जाना है, उसे बताया जाएगा कि वह किस किस पीसीसी सदस्य के हस्ताक्षर करवाए।

जहां तक कांग्रेस में चुनाव के तरीके की बात की जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की शुरुआत सदस्यता अभियान से होती है, जो लगभग एक साल चलता है। इसके पूरा होने बाद बूथ और ब्लॉक कमेटी बनाई जाती है। इसके बाद जिला संगठन बनाया जाता है। संविधान के मुताबिक, इन कमेटियों का गठन भी चुनाव के आधार पर होना चाहिए। ब्लॉक और बूथ कमेटी मिलकर ही प्रदेश कांग्रेस को चुनते हैं।

हर ब्लॉक से एक पीसीसी प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। इसके बाद हर 8 पीसीसी पर एक केंद्रीय कांग्रेस कमेटी प्रतिनिधि चुना जाता है। एआईसीसी और पीसीसी का अनुपात एक और आठ का होता है। पीसीसी प्रतिनिधियों के वोटों से ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और पार्टी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। वर्ष 2017 में हुए संगठन चुनावों के दौरान पीसीसी की तादाद 9000 थी, तो एआईसीसी प्रतिनिधियों की संख्या 1500 थी। इस बार पीसीसी और एआईसीसी के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने वाली है।

कांग्रेस के संविधान के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो जो प्रक्रिया तय है उसके अनुरूप काम नहीं हुआ है क्योंकि ना तो ब्लॉक स्तर पर किसी तरह के चुनाव हुए हैं ना ब्लॉक प्रतिनिधियों की तरफ से जिला प्रतिनिधि चुने गए हैं और ना जिला प्रतिनिधियों और ब्लॉक अध्यक्षों की ओर से प्रदेश प्रतिनिधि चुने गए हैं ऐसे में चुनाव की जो प्रक्रिया है, पूरी तरह से मनोनयन के हिसाब से ही चलेगी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस में चुनाव की जो प्रक्रिया ब्लॉक के चुनाव के साथ शुरू होनी चाहिए, वह नहीं होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के जरिए विपरीत तरीके से हो रही है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधियों की सूची जारी नहीं करने को लेकर वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, शशि थरूर सहित अन्य लोग भी सवाल उठा चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि जब प्रदेश प्रतिनिधियों की सूची जारी ही नहीं हो रही, तो जो भी नेता चुनाव लड़ने का इच्छुक है,वह अपना नामांकन कैसे दाखिल कर पाएगा।

राहुल गांधी ने अभी पूरे पत्ते नहीं खोले हैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के बारे में

- **राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि, उन्होंने, अध्यक्ष पद के चुनाव में क्या करना है यह तय कर लिया है और चुनाव के समय इसका जवाब दे देंगे।**
- **राहुल गांधी ने तमिलनाडू में ''भारत जोड़ो यात्रा'' के दौरान अध्यक्ष बनने को लेकर संशय बरकरार रखते हुए कहा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा या नहीं, पार्टी अध्यक्ष का जब चुनाव होगा तब यह स्पष्ट हो जाएगा। मैंने निर्णय ले लिया है। मैं बहुत स्पष्ट हूं और जब चुनाव होंगे तब जवाब दूंगा।**

पुलियुरकुरुचि, (तमिलनाडु), 9 सितंबर (वार्ता)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए अगले सप्ताह हो रहे चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर संशय बरकरार रखते हुए कहा है कि वह इस बारे में 'निर्णय ले चुके हैं' और चुनाव के समय इसका जवाब दे देंगे।

गांधी ने 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान शुक्रवार को यहां खचाखच भरे संवाददाता सम्मेलन में उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने सम्बन्धी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया लेकिन पहली बार इस बारे में बोलते हुए कहा कि,उनकी सोच स्पष्ट है और वह अपना निर्णय ले चुके हैं।

उन्होंने अध्यक्ष बनने को लेकर संशय बरकरार रखते हुए कहा,मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा या नहीं, पार्टी अध्यक्ष का जब चुनाव होगा तब यह स्पष्ट हो जाएगा। मैंने निर्णय ले लिया है। मैं बहुत स्पष्ट हूं और जब चुनाव होंगे तब जवाब दूंगा।

गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है और 17 सितंबर को जरूरत पड़ने पर अध्यक्ष पद के लिए मतदान होना है। मतदान के दौरान पार्टी की 'भारत जोड़ो यात्रा' कर्नाटक में होगी इसलिए वहीं से मतदान करने वाले डेलीगेट के लिए मतदान की व्यवस्था की जा रही है।

कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरु हुई भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन उमड़े जनसैलाब को देखकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) घबरा गई है इसलिए उसके नेताओं ने उल्टे सीधे बयान देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस बारे में कहा कि भाजपा पद यात्रा में उमड़ रही भीड़ को देख कर परेशान है और घबराहट में उसके नेता इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

उन्होंने यात्रियों के ठहरने के लिए विश्राम के लिए शिविर स्थल पर की गई कंटेनर व्यवस्था की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें कहीं कोई लग्जरी सुविधा नहीं है लेकिन जो लोग फाइव स्टार होटलों में रहते हैं उन्हें इन कंटेनरों में भी पांच सितारा होटलों की लग्जरी नजर आ रही है और यही वजह है कि भाजपा पद यात्रा को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर रही है।

गुमनाम पार्टी को 90 करोड़ रुपये चंदा

आयकर विभाग की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा सामने आया

- **जनतावादी कांग्रेस पार्टी नाम से 2015 में रजिस्टर हुई इस पार्टी का हैड ऑफिस मुंबई की एक झुग्गी झोपड़ी में है।**
- **आयकर विभाग को शक है कि, हवाला रैकेट के जरिए आई रकम राजनीतिक दल को ट्रांसफर की गई है। इससे शक और गहरा गया है।**

मुंबई, 9 सितम्बर। मुंबई की एक झुग्गी बस्ती से चलने वाली एक राजनीतिक पार्टी को मिले करोड़ों के चंदे ने आयकर विभाग के कान खड़े कर दिए हैं। हाल ही में देश भर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से छापेमारी की गई थी। इसी दौरान इस राजनीतिक दल के बारे में भी खुलासा हुआ है। जनतावादी कांग्रेस पार्टी नाम के इस दल का मुख्यालय चूनाभट्टी इलाके की एक झुग्गी बस्ती में स्थित है। जानकारी सामने आई है कि 2015 में बनी जनतावादी कांग्रेस पार्टी को कोई छोटी राशि नहीं बल्कि 90 करोड़ रुपये का चंदा मिला है। आयकर विभाग को शक है कि हवाला रैकेट के जरिए आई रकम राजनीतिक दल को ट्रांसफर की गई है। इससे शक और गहरा गया है। जनतावादी कांग्रेस पार्टी पंजीकृत दल है, लेकिन महाराष्ट्र या फिर मुंबई की सियासत में इसका कभी कोई रोल नहीं रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जनतावादी कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ रुपये का दान किसने दिया? जो एक चाली में दो मंजिला कमरे से चलती है और पार्टी के सिंबल के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। इस बारे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष काटके ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को 90 करोड़ रुपये का चंदा मिला। यह सारा पैसा पार्टी के काम में खर्च किया गया। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है।

पार्टी अध्यक्ष संतोष काटके ने कहा कि मैंने खर्च का सारा ब्योरा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। हालांकि, आयकर विभाग ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। आयकर विभाग के अफसरों का कहना है कि जनतावादी कांग्रेस पार्टी द्वारा दिखाए गए सभी खर्च विवरण फर्जी हैं।

बिलकीस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ज्ञातव्य है कि 2020 के दंगों के दौरान, बिलकीस के साथ हुये गैंग-रेप तथा उसके परिजनों की हत्या के अपराधियों को हाल ही में 15 अगस्त रिहा कर दिया गया था।

तीनों महिलाओं महुआ मोईत्रा, सुभाषिनी अली और प्रो. रूप रेखा वर्मा द्वारा दायर याचिकाओं में कहा गया था कि वे उस सक्षम अधिकारी के उस आदेश को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें गुजरात में जघन्य अपराध करने वाले इन 11 लोगों की उम्र कैद को रद् कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि उनके अपराध की जाँच हुईथी तथा इसलिये केन्द्र से विचार विमर्श किये बिना, गुजरात सकार के स्तर पर ही माफी दे दिया जाना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रॉसीजर, 1973 की धारा 435 के अनुसार अनुमति-योग्य नहीं हैं।

याचिका में कहा गया है कि यह माफी जनहित के पूरी तरह विरूद्ध समग्र एवं सार्वजनिक चेतना को आघात पहुँचाने वाली होने के साथ पीड़िता के हितों के पूर्णत: विरूद्ध होगी, जिसके परिवार ने उसकी सुरक्षा के लिये चिन्ता जताते हुये, सार्वजनिक रूप से बयान दिये हैं।

ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को कड़ी नसीहत दी

ममता बनर्जी ने खुलकर कहा, सिर्फ अपने क्षेत्र पर ध्यान दो, संगठन के किसी भी मामले में दखल मत दो

- **गौरतलब है कि, महुआ मोइत्रा अक्सर इस तरह की बयानबाजी करती हैं जिससे पार्टी को सार्वजनिक तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ता है।**

कोलकाता, 9 सितम्बर। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपनी पार्टी की आक्रामक तेवर रखने वाली सांसद महुआ मोइत्रा को नसीहत दी है। उन्होंने महुआ से साफ कहा है कि वह अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें और संगठन के कामकाज में दखल न दें। महुआ मोइत्रा कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। कोलकाता में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की मीटिंग में नादिया की करीमपुर विधानसभा सीट को लेकर कहा कि वह यहां के मामलों को मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर पर ही छोड़ दें। दरअसल करीमपुर से 2016 में महुआ मोइत्रा विधायक चुनी गई थीं और इसके चलते वहां से उनका खास लगाव रहा है। वह वहां के मामलों में भी दखल देती रही हैं, जिसे लेकर अब ममता बनर्जी ने उन्हें चेताया है।

टी.एम.सी. ने महुआ मोइत्रा को लोकसभा चुनाव में उतार दिया था और फिर उपचुनाव में बिमलेंदु सिन्हा रॉय को जीत मिल गई थी। इसके अलावा वहां का प्रभारी अबू ताहिर को बनाया गया था। इसी पर बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि करीमपुर विधानसभा क्षेत्र अब महुआ मोइत्रा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है बल्कि अबू ताहिर उसके प्रभारी हैं। वह वहां के मामलों को देख लेंगे। दरअसल बीते कुछ दिनों में महुआ मोइत्रा की शिकायत की गई थी। इसमें कहा गया था कि महुआ करीमपुर के मामलों में दखल देती हैं और समानांतर संगठन चलाती हैं। इसमें कुछ नेताओं और इलाके के अधिकारियों का सहयोग है। यही नहीं उन पर पार्टी की गाइडलाइंस को भी नजरअंदाज करने के आरोप लगते रहे हैं।

महुआ मोइत्रा के दखल से स्थानीय विधायक समेत कई नेता नाराज थे। अब ममता बनर्जी की ओर से महुआ को फटकार लगाए जाने पर विधायक बिमलेंदु सिन्हा रॉय ने खुशी जताई है और कहा है कि यह करीमपुर के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। सिन्हा ने कहा कि महुआ मोइत्रा करीमपुर में आकर सिर्फ समस्याएं ही पैदा करती हैं।

उनकी मौजूदगी के चलते करीमपुर में संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है। सिन्हा रॉय ने कहा, मैं करीमपुर से दो बार का विधायक हूं। वह अक्सर यहां आती हैं, लेकिन मुझे इग्नोर किया जाता है। वह अपने पालतू बी.डी.ओ. के जरिए यहां काम करती हैं। वह मुझे यहां काम तक नहीं करने देती हैं। इसलिए यह पूरा मामला ममता बनर्जी तक पहुंचा।

मोदी सत्यपाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के अड़ानी नामक मित्र हैं, जो पिछले पांच वर्षो में एशिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। अडानी को पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और बड़ी परियोजनाएं दी गई हैं। एक तरह से देश को बेचने की योजना है, लेकिन हम ऐसा होने नही देंगे।'' मलिक ने आगे यहां तक कहा था कि ''अडानी ने पानीपत में एक बड़ा गोदाम बनाया है, जहां उन्होंने सस्ती दरों पर खरीदे गए गेहूं की जमाखोरी कर रखी है,लेकिन जब मंहगाई बढ़ेगी तब वे गेहूं बेच देंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री के मित्र मुनाफा कमाते हैं और किसान परेशानियां झेलते हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके विरूद्ध संघर्ष होगा।'' मलिक के आवेगों के प्रति प्रधानमंत्री की नर्म प्रतिक्रिया संबंधी अटकलों पर लौटें तो, एक तर्क तो यह है कि मलिक की मिसाइलें पूर्व नियोजित हैं और उनका उद्देश्य शासन तंत्र के भीतर प्रधानमंत्री की आलोचना को नियंत्रित रखना है। दूसरा यह कि मलिक को आंदोलनरत जाट किसानों के बीच भाजपा के एक संभावित दूत के रूप में भविष्य की भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है, और तीसरा, राज्यपाल मलिक को मनमाफिक बोलने की छूट प्रदान कर प्र.मंत्री की उदार छवि पेश की जा रही हैं।

क्वीन ऐलिज़ाबैथ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के बाद ब्रिटेन में अब कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जानकारी के अनुसार सबसे पहले ब्रिटेन में रोजमर्रा की वस्तुओं में कई बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि बैंक नोटों, लेटरबॉक्स और टिकटों पर क्वीन ऐलिज़बैथ की छवि और प्रतीक चिन्ह को नए राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ बदल दिया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश मुद्रा को रातोंरात नहीं बदला जाएगा। इस बदलाव में वर्षों लगेंगे, क्योंकि नए सिक्के और नोट राजा के चेहरे से बनाए जाते हैं और अन्य धीरे-धीरे प्रचलन से हटा दिए जाते हैं। एक और बदलाव यह होगा कि, जहां सिक्कों पर रानी की छवि दाईं ओर होगी, वहीं नए में राजा को बाईं ओर मुंह करके दिखाया जाएगा। यह 17 वीं शताब्दी से एक परंपरा के कारण है।

महारानी ऐलिज़ाबैथ द्वितीय ने सर्वाधिक 70 साल तक ब्रिटेन में शासन किया। वे ब्रिटेन में बेहद लोकप्रिय भी रहीं। भारत से ऐलिज़ाबैथ का विशेष लगाव रहा।

ब्रिटेन में आधिकारिक हलकों में महारानी के निधन को ''ऑपरेशन लंदन ब्रिज'' कोडनेम दिया गया है। यह एक तरह का प्रोटोकॉल है, जिसे बकिंघम पैलेस के गुरुवार को 96 वर्षीय महारानी के निधन की घोषणा के बाद लागू किया गया। इसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। इसके साथ ही ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड भी लागू हुआ, जिसके तहत क्वीन ऐलिज़ाबैथ द्वितीय के बेटे और उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स को 73 साल की उम्र में महाराज चार्ल्स तृतीय के रूप में देश की राजगद्दी पर विराजमान हुए।

किंग चार्ल्स बिना पासपोर्ट के विदेश यात्रा करेंगे। उन्हें अपने नाम पर जारी किए गए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा ब्रिटेन में राजा ही एकमात्र व्यक्ति होंगे जो बिना लाइसैंस के गाड़ी चला सकते हैं।

ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स वोट नहीं देंगे। वे ना ही चुनाव के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं। राज्य के प्रमुख के रूप में उन्हें राजनीतिक मामलों में सख्ती से तटस्थ रहना होगा। वे संसदीय सत्रों के औपचारिक उद्घाटन में शामिल होते हैं। संसद से बने कानून को मंजूरी देते हैं। साथ ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ साप्ताहिक बैठकें करते हैं।

''क्वीन'' को ''हैड ऑफ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कैमक स्ट्रीट पर उनका भव्य बंगला आज भी मौजूद है। पुराने ब्रिटिश सम्पर्कों को कुछ मान्यता भी थी। सौ साल पुराने अग्रणी टी ऑक्शन कम्पनी थॉमस एंड कम्पनी को कलकत्ता में ही विभिन्न रॉयल इवैन्ट्स के आमंत्रण लगातार प्राप्त होते थे।

कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं, जो पूरे युग में छाए हुए हैं। क्वीन विक्टोरिया और क्वीन ऐलिज़ाबेथ ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। काफी पहले क्वीन ऐलिज़ाबेथ प्रथम ऐसी ही रही होंगी, लेकिन वह काफी पहले की बात है।

यदि क्वीन ऐलिज़ाबेथ द्वितीय ने अपने शासन की शुरुआत आत्मविश्वास के एक युग से की थी तो उनके शासन का अन्त भी महा अनिश्चितता के समय में हुआ। चालीस के दशक के अंत का उनका ग्रेट ब्रिटेन भविष्य का ''लिटिल इंग्लैंड'' बनने की ओर अग्रसर था। हालांकि स्कॉटलैण्ड का दु:ख देखने से वे बच गईं, जो युनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र होकर एक सार्वभौमिक राष्ट्र बन गया।

उस साम्राज्य के अवशेष के रुप में अब निस्तेज सा कॉमनवैल्थ बचा है, जो मुख्यत: खेल-मंच के रुप में असित्व में है। इंग्लैंड आज एक ऐसे उम्रदराज राष्ट्र के रुप में रह गया है, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कोई प्रभाव नहीं है। स्वयं को यूरोपीय संघ से अलग कर लेने का उसका निर्णय उसके लिये अंतिम आघात सिद्ध हुआ है।

पूर्व साम्राज्य अब वापसी के लिये हाथ-पैर मार रहा है। अप्रवास ने इंग्लैंड की रंगत बदल दी है। अब अंग्रेज राजनेताओं की राजनैतिक वौद्धिकता भी गायब होती जा रही है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि महारानी के पूर्व विदेश सचिव को रुस के विदेश सचिव ने झिड़कते हुये बहरा तक कह दिया था।

राज परिवार कभी भी विवादों एवं लज्जास्पद स्थितियों दूर नहीं रहा है। महारानी के दूसरे बेटे पर हाल ही में एक बदनाम सैक्स-ऑफेन्डर के साथ मिली भगत के आरोप लगे थे तथा उसके शिकारों से बहुत सारे पैसे के लेन-देन की बातें सामने आई थीं। अविश्वसनीय रुप से दुखद डायना-प्रकरण का उल्लेख करने की तो शायद जरुरत ही नहीं है।

इस प्रकार की तकलीफों के बावजूद, अपनी गरिमा तथा राजसी ईमानदारी के उच्च स्तरों के मानदंडों को बनाये रखना महारानी ऐलिज़ाबेथ की एक मुख्य विशिष्टता रही। कई मामलों में उनकी खामोशी तथा उनकी आत्मसंयम युक्त सहनशक्ति उनकी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इस प्रकार के आत्म-संयम तथा विरोधियों से डरने के इनकार के जरिये, उन्होंने इंग्लैंड को एक ऐसा अवलम्ब एवं सबल दिया, जिसकी, एक राष्ट्र के रुप में बने रहने के लिये, उसे बहुत जरुरत थी। अनेकानेक प्रकार की तकलीफों के बीच स्थायित्व एवं संरक्षण का जो भाव उन्होंने प्रदर्शित किया, उसके लिये उनके देश को उनके प्रति श्रद्धावनत होना चाहिए।

नूपुर की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ की गई कथित टिप्पणियों को लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी।

सी.जे.आई. ललित ने कहा कि ''यह बात बहुत सरल एवं अहानिकर प्रतीत होती है किन्तु इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

तेलंगाना भी पश्चिम बंगाल ...

चीन के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस बढ़ती चिंता को रेखांकित करते हैं कि चीन मुक्त पूंजीवाद के युग से तेजी से पीछे हटकर एक सरकार केन्द्रित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें आर्थिक विकास के बजाए राजनीति और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है।

त्यागपत्र: कुछ अन्य अति धनाढ्य उद्यमियों ने हाल के महीनों में अपने शीर्ष पदों से इस्तीफे दिए हैं, जिनमें अलीबाबा के सह-संस्थापक जैक मा, अलीबाबा की प्रतिद्वंद्वी कम्पनी पिन्ड्युओड्ओ के संस्थापक कोलिन हुआंग और टिक टॉक की पेरेन्ट कम्पनी वाइट डांस के संस्थापक झैंग झिंमिग शामिल हैं।

विदेश गमन: एक प्रमुख टैक एन्टरप्रोन्योर एवं वैंचर कैपिटलिस्ट झाओ हैंग ने शंघाई लॉकडाउन के दौरान हाल ही कैनेडा पलायन किया। वहां उन्होंने चीन की वर्तमान नीतियों की भर्त्सना की।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्हें अलग-थलग कर रही है तथा उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर राज्यपाल-कार्यालय की उपेक्षा कर रही है तथा विभिन्न मुद्दों से संबंधित जो जानकारियाँ एवं रिपोर्ट मँगवाई जा रही है, राज्य-सरकार उन्हें देने से इनकार कर रही है। उन्होंने प्रैस-कॉन्फ्रेंस में कहा कि ''राज भवन एक अछूत स्थान बन गया है।'' उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह कदम दोषपूर्ण था कि वे दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों की उस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित नहीं हुये, जो केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई थी।

राज्यपाल ने कहा कि तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश के साथ चल रहे विवादों के समाधान का एक स्वर्णिम अवसर गँवा दिया। उन्होंने प्रश्न किया कि मुख्यमंत्री इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में आखिरकार उपस्थित क्यों नहीं हुये। उन्होंने इस तथ्य पर भी कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की कि मुख्यमंत्री उस परम्परागत ''ऐट होम रिसेप्शन'' में उपस्थित नहीं हुये, जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राज्यपाल ने दिया। रिपोर्टों के अनुसार, सी.एम.ओ. ने कह दिया था कि मुख्यमंत्री उस समारोह में उपस्थित होंगे, लेकिन अंतिम क्षणें में राज भवन को सूचित किया गया कि वे इस समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे।

उन्होंने जोर देते हुये कहा कि जब से उन्होंने यह पद सँभाला है, तभी से उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक राज्यपाल एवं महिला होने के नाते, वे सम्मान की हकदार हैं लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार राज्यपाल के पद की गरिमा को क्षति पहुँचाने पर तुली हुई है। उनकी नाराजगी समझ में आने योग्य है। अभी हाल ही में, उन्हें मेदरम नामक स्थान पर आयोजित सामाजिक-धार्मिक समारोह ''सम्मक्का-सरक्का'' जातरा में पहुँचने के लिये हेलिकॉप्टर उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया गया तथा उन्हें सड़क-मार्ग से जाना पड़ा। उस समारोह में उनके स्वागत के लिये कलेक्टर तक मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित नहीं किया तथा जब राज भवन ने इस दिशा में पहल की, तो मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं हुये।

अब, मुख्यमंत्री तथा सरकार के लिखफ उनके द्वारा की गई इस कटु निन्दा के बदले में, अगर ज्यादा नहीं तो इसके बराबर ही तीखा हमला उनकी कार्यशैली को लेकर सरकार द्वारा उन पर किया जा रहा है। राज्यपाल की तीखी आलोचना करते हुये कहा जा रहा है कि वे केन्द्र सरकार की एजेंट तथा एक भाजपा नेता की तरह काम कर रही हैं।

के.सी.आर. की पुत्री तथा एम.एल.सी. कविता कलावन्तुला ने राज्यपाल सौंदरराजन पर कड़ा प्रहार करते हुये कहा है कि उन्होंने राज भवन को राजनैतिक स्थल बना दिया है। राज्यपाल पर आरोप लगाया कि सरकार एवं मुख्यमंत्री को दोषी ठहराने तथा उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। और इसके बाद, विभिन्न मंत्रियों ने भी आलोचनाओं की गोला-बारी शुरु कर दी है तथा कहा है कि राज्यपाल, राज्यपाल पद के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम कर रही हैं।

बाल कल्याण मंत्री सतयवती राठौड़ ने कहा, ''केवल इन्हीं राज्यपाल के कार्यकाल में समस्याएं पैदा हो रही हैं। इनसे पहले, और भी राज्यपाल रहे हैं, जिनके साथ सरकार बिना किसी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी के साथ काम किया है।''

पूजा स्थल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है कि ''कट्टर एवं नृशंस हमलावरों तथा कानून तोड़ने वालों'' द्वारा किये अतिक्रमण के फलस्वरूप अस्तित्व में आये पूजा स्थलों तथा तीर्थों की स्थिति को यथावत बनाये रखने के लिये, 1991 के कानून में, 15 अगस्त 1947 की ''कट-ऑफ डेट'' मान लिया जाना स्वेच्छाचारिता तथा विवेकपूर्ण है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908